प्रशासन को मौका मिला। उसने कहा कि बेहद खुलेपन की वजह से यह सब हुआ है और कुछ सख्त कानून बनाये जायेंगे। इस घटना के बाद निश्चित तौर पर प्रशासन को अपने खतरनाक मंसूबे पूरे करने के लिए एक आड़ मिल गयी।

लेकिन एक और कारण ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह है जे.एन.यू. के छात्रों की आबादी के संघटन और साथ ही साथ छात्रों की मानसिकता में आया बदलाव। छात्रों में कैरियरवाद का प्रभाव बेहद तेजी से बढ़ा है। पहले यहां के छात्र शिक्षा क्षेत्र की बड़ी घटनाओं पर ही नहीं बल्कि सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर भी काफी जागरूक होते थे और हर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय घटना पर प्रतिक्रिया करते थे। लेकिन आज छात्रों में अपने आप को सामाजिक-राजनीतिक विसंगतियों से काटकर कैरियर बनाने में जुट जाने का रुझान बेहद मजबूत हुआ है। यह रुझान छात्रों के जुझारूपन को कुंद बना रहा है और आम लोगों के संघर्ष से उन्हें काट रहा है। संसदीय वामपंथी पार्टियों से जुड़े छात्र संगठनों के क्रियाकलापों ने भी जे.एन.यू. परिसर के माहौल को गैर-राजनीतिक और 'पैस्सिव' बनाने में भूमिका निभाई है। इन्हीं कारणों से यहां उन फासीवादी हिन्दुत्व ताकतों का उदय हुआ जिनका पहले परिसर में नामोनिशान भी नहीं था।

इस तरह की और भी वस्तुगत और मनोगत परिस्थितियां तैयार हुई हैं जिससे इस तरह की आचार-संहिता लागू करने का साहस प्रशासन में पैदा हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भाजपा सरकार का बाजारवाद के नये प्रतिमान स्थापित करना परिसर में निरंकुशता और गैर-जनतांत्रिक माहौल कायम करने से सीधे-सीधे जुड़ा हुआ है। शिक्षा का बाजारीकरण लगातार बढ़ी हुई फीस का बोझ छात्रों के मत्थे मढ़ रहा है, गरीब छात्र शिक्षा से दूर किये जा रहे हैं और देश में लुटेरी आर्थिक नीतियां कहर बरपा कर रही हैं। ऐसे में छात्रों में असंतोष और गुस्से का पनपना स्वाभाविक है। लेकिन भारतीय प्रशासक नहीं चाहते कि किसी भी तरह जे.एन.यू. में यूनाम या तेहरान दोहराया जाये।

1 अगस्त को जे.एन.यू. छात्रसंघ के बैनर तले छात्रों ने संगठित होकर आचार-संहिता की प्रतियां जलायीं और कुलपति के खिलाफ नारे लगाये। छात्रों ने कहा कि अगर इन गैर-जनतांत्रिक नियमों को उन पर थोपने की कोशिश हुई तो वे आन्दोलन करेंगे।

लेकिन अगर जे.एन.यू. के छात्रों को इन साजिशों को शिकस्त देनी है तो उन्हें देश भर के छात्रों के संघर्षों से ऐक्यबद्ध होना होगा क्योंकि परिसर में जनतंत्र की हत्या पहली बार नहीं हो रही है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में इसी वर्ष छात्र संघ को नाकारा बना देने के लिए एक निरंकुश आचारसंहिता लागू की जा चुकी है। कई और विश्वविद्यालयों में इसकी तैयारी है। वे अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों के संघर्षों से कटकर नहीं रह सकते, उनसे जुड़कर ही राष्ट्रीय स्तर पर इन छात्र-विरोधी नीतियों और साजिशों से लड़ सकते हैं। ●

शासन के खैरख्वाह एक कुलपति की कारस्तानियां

"उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने" के नाम पर मौजूदा सत्र से सरकार उ.प्र. के कई विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों में भारी शुल्क वृद्धि (चार गुने-पांच गुने) के जिस प्रस्ताव को लागू करना चाहती थी, फिलहाल उसे वापस ले लिया गया है। विगत दिनों लखनऊ में सम्पन्न प्रदेश के कुलपतियों के सम्मेलन में इस प्रस्तावित शुल्क वृद्धि पर सरकार के प्रतिनिधियों ने चर्चा तक नहीं की। दरअसल, शुल्क वृद्धि की खबर सुनकर प्रदेश भर में छात्र-युवा आन्दोलनों की सुगबुगाहटों से सरकार ने यह नतीजा निकाला कि आसन्न विधान सभा चुनावों के मद्देनजर शासक पार्टी (मुख्यतः भाजपा) की चुनावी सेहत के लिए यह अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए, फिलहाल सरकार ने मौजूदा सत्र में शुल्क वृद्धि न लागू करने का फैसला किया। लेकिन, शासन के एक खैरख्वाह कुलपति सरकार की चुनावी मजबूरी से बेपरवाह होकर शासन के प्रस्तावों को अपने स्तर पर सीमित पैमाने पर लागू करने पर तुले हुए है। जी हां, यह गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जनाब राधे मोहन मिश्र हैं।

कुलपति सम्मेलन से वापस लौटने के तत्काल बाद उन्होंने विश्वविद्यालय कार्य परिषद की एक आपात बैठक बुलायी और शासन की घोषित मंशा के विपरीत सभी कक्षाओं के वार्षिक शुल्क में दो सौ रुपये की वृद्धि करने का प्रस्ताव पारित करा लिया। हालांकि इस मसले पर कार्यपरिषद के भीतर मतैक्य नहीं था। कार्य परिषद के एक सदस्य भोलेन्द्र सिंह ने तो प्रेस बयान भी जारी किया कि वे शुल्क वृद्धि को उचित नहीं मानते। कुलपति ने कार्यपरिषद को शासन की मंशा के बारे में गलत सूचना देकर शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव पास करा लिया। उन्होंने कार्य परिषद की बैठक फिर से बुलाने की बात कही।

यह तो कुलपति महोदय की राजभक्ति और छात्र विरोधी रवैये की एक बानगी है। पदभार ग्रहण करने से लेकर आज तक उन्होंने घोर छात्र-विरोधी-कर्मचारी विरोधी फरमानों की झड़ी लगा दी है। विश्वविद्यालय निरंकुशशाही की प्रयोगशाला बन गया है। छात्रों-कर्मचारियों के जनतांत्रिक आन्दोलनों पर लाठी चलवाना उनकी कार्यशैली का अभिन्न अंग है। अभी पिछले दिनों कोर्स पूरा न होने के कारण परीक्षा टलवाने के लिए वार्ता करने गये छात्र प्रतिनिधियों को उन्होंने माफिया तक कह डाला। यह भी कहा कि वे विश्वविद्यालय में जनतांत्रिक विरोध और आन्दोलनों की संस्कृति को ही खत्म कर देना चाहते हैं। मौजूदा सत्र शुरू होते ही परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार को दंगा नियंत्रक वाहन 'वज्र' सहित खाकी वर्दीधारियों ने अपने कब्जे में ले रखा है और कैम्पस में आतंक राज कायम करने की नयी-नयी कवायदें भी शुरू हो चुकी हैं।

मौजूदा सत्र में विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों को मिलाकर सोलह हजार से भी अधिक सीटों की कटौती कर दी गयी है और सान्ध्यकालीन कक्षाओं को भी खत्म कर दिया गया है। हालांकि सीटों में कटौती के सवाल पर महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने कुलपति के आदेश का पालन करने से इंकार कर दिया है, लेकिन कुलपति महोदय अभी अपनी मर्जी पर डटे हुए हैं।

मौजूदा सत्र शुरू होते ही कुलपति ने यह फरमान जारी किया कि परिसर की दीवारों पर किसी तरह के पोस्टर न लगाये जायें। जो कोई भी छात्र, संगठन, या संस्था पोस्टर चिपकायेगा उसे संज्ञेय अपराधी ठहराते हुए उचित सजा दी जायेगी। साथ ही, जिस कर्मचारी की ड्यूटी अवधि में पोस्टर चिपका पाया जायेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी।

ऐसे ही घोर निरंकुश फरमानों की झड़ी लगाकर कुलपति महोदय शासन की नजरों में चढ़े रहना चाहते हैं। छात्र-कर्मचारी-शिक्षक सभी कुलपति महोदय के फरमानों से त्रस्त हैं। गुस्सा किस रूप में फूटेगा, क्या अंजाम होगा, यह तो समय ही बतायेगा, लेकिन अतीत बताता है कि तानाशाहों का अंजाम अच्छा नहीं हुआ करता।

● आह्वान संवाददाता

जे.एन.यू. ...